प्रेषक.

यू० सी० घ्यानी, सचिव. न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तरांचल शासन ।

सेवा में.

महानिबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नेनोताल ।

न्याय अनुभागः

देहरादुन :दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 विषय: विस्ताय वर्ष 2004-2005 में न्यायालय परिसर सिविल जज (जू0डि0), रामनगर, जनपर

नैनीताल की पेयजल योजना के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1324/IX-(b)-10/2004, दिनांक 18.6.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यायालय परिसर सिविल जज (जू०डि०), रामनगर, जनपद मैनीताल की पंयजल योजना के निर्माण हेतु २० 11.42,000/-के आगणन के विरुद्ध टी०५०सी० द्वारा परीक्षणीपरान्त संस्तुत रु० 10,96,000/- (रुपये दस लाख छयानच्चे हजार मात्र) की धनराशि के लागत के आगणन को प्रशासकीय एवं विलीय स्वीकृत्ति प्रदान करते हुए महामहिम राज्यपाल इतनी हों धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन सहये प्रदान करते है:-

- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा (1) स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिङ्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर निवमानुसार अधीक्षण अभियना का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गटित कर सक्षम (2) प्राधिकारी से प्राविधिक स्योकृति प्राप्त की जाय, तद्यंपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- कार्य पर उतना हो व्यय किया जाय जितना कि नाम्से के अन्तर्गत स्वोकृत है, स्वीकृत (3) नाम्स् से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
- एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति निर्माण (4) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।
- उपर्युक्त स्बोकृति इस शर्त के अधीन दो जाती है कि व्यय से पूर्व वजट मैनुआन, वित्तीय (5) इस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय ।
- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा (6) लिया जाय । निरीक्षण के पश्चात् निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया
- (7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकरोकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरुप हो कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

- (8) आगणन में धनराशि जिस मद हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में आवंटित न की जाय । उक्त स्वीकृति में साज-सज्जा की यहें सम्मिलित नहीं है ।
- (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (10) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना मुनिश्चित किया जाय, अन्यथा को स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (11) कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुये इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.3.2005 तक मुनिश्चित कर लिया जाय ।
- (13) कार्य को समयचद्भता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी ।
- 2- इस सम्बन्ध में होनं वाला व्यय चान् विलोग वर्ष 2004-2005 की आय-व्ययक को अनुवान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शोर्षक "4059-लोकॉनर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-आयोजनागत-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोविधानित योजनाये-01-न्यायिक कार्य हेतु भवनी का निर्माण (50 प्रतिशत केन्द्रोश)-24-वृहत् निर्माण कार्य" छे नामें हाला जायेगा।
- 3- यह आदेश विला विभाग के अशासकीय संख्या-1611/बिला अनुभाग-3/2004 दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

धवदीय, (यू० सी० ध्यानी) सचिव ।

संख्या-38-दो-(1)(1)/छत्तोस्(1)/न्याय अनुभाग/2004-तद्दिनांक ।

प्रतिसिपि निम्नसिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित:

- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तराचंल,माजरा, देहराद्व ।
- जिला जज, नैनीवास।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, अल्पोड्ग ।
- मुख्य अभियन्ता, लोक निमांण विभाग, अल्मोडा ।
- श्री एला एमा पन्त, अपर सचिव, विला, उत्तरांचल शासन ।
- 7. नियोजन विभाग, उत्तरांचलु-शासन ।
- 8. विता अनुभाग-3/ कें करे और
- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से. १९६६के पालीबाल) अपर सचिव ।